प्रारंभिक परीक्षा

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM-VIKAS) योजना

संदर्भ

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) कोट्टायम में **PM-VIKAS** कौशल विकास और महिला उद्यमिता कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM-VIKAS) के बारे में -

- **यह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय (MoMA) के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।**
- **इसका उद्देश्य समावेशी विकास के माध्यम से अल्पसंख्यक और कारीगर समुदायों को सशक्त बनाना है।**
- PM-VIKAS एक एकीकृत योजना है जिसमें MoMA की (5) मौजूदा योजनाओं को शामिल किया गया है, जैसे सीखो और कमाओ, USTTAD, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल।
- **योजना घटक:**
    - **कौशल एवं प्रशिक्षण:** इसमें पारंपरिक (कला एवं शिल्प) और गैर-पारंपरिक (एनएसक्यूएफ अनुरूप) कौशल प्रशिक्षण शामिल है।
    - **नेतृत्व एवं उद्यमिता:** विशेष रूप से महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास और उद्यमिता समर्थन पर ध्यान केंद्रित करता है।
    - **शिक्षा:** स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए ओपन स्कूलिंग (8वीं, 10वीं और 12वीं) के अवसर प्रदान करता है।
    - **बुनियादी ढांचे का विकास:** कला, शिल्प, पर्यटन और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए "विश्वकर्मा गांवों" (हब और स्पोक मॉडल) का विकास।

अल्पसंख्यक -

- **भारत का संविधान "अल्पसंख्यक" शब्द को परिभाषित नहीं करता है।**
- केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा-2(c) के तहत छह समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया है।
    - मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन।
    - 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत 19.3% है।

स्रोत: द हिंदू

जैव अपशिष्ट से हरित हाइड्रोजन

संदर्भ

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु में जैव-अपशिष्ट से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के नवाचार की सराहना की।

प्रक्रिया अवलोकन -

- **बायोमास गैसीकरण:** कृषि अपशिष्ट को थर्मोकेमिकल गैसीकरण के अधीन किया जाता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), हाइड्रोजन (H_2), मीथेन (CH_4) आदि गैसों का मिश्रण उत्पन्न होता है।
- **जल-गैस विस्थापन अभिक्रिया:** CO जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके अधिक हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है।
- **हाइड्रोजन पृथक्करण एवं शुद्धिकरण:** गैस मिश्रण से उच्च शुद्धता वाले हाइड्रोजन (99%+) को अलग करने के लिए उन्नत निस्पंदन एवं पृथक्करण प्रणालियों का उपयोग किया जाता है।
- **कार्बन-नकारात्मक आउटपुट:** उत्पादित प्रत्येक किलोग्राम हाइड्रोजन के लिए, वायुमंडल से 1 किलोग्राम से अधिक CO_2 हटा दिया जाता है, जिससे यह प्रक्रिया कार्बन-नकारात्मक हो जाती है।

महत्व -

- **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का समर्थन:** यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन(NGHM) के निम्नलिखित लक्ष्यों के अनुरूप है:
    - 5 एमएमटी वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन
    - 125 गीगावाट अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा
    - ₹8 लाख करोड़ का निवेश और 6 लाख से अधिक नौकरियाँ
    - प्रति वर्ष 50 एमएमटी CO_2 उत्सर्जन को कम करने में प्रत्यक्ष योगदान।
- **कार्बन-नकारात्मक नवाचार:** इलेक्ट्रोलिसिस (जो नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने पर शुद्ध-शून्य है) के विपरीत, यह प्रणाली हाइड्रोजन उत्पन्न करते समय CO_2 को हटाती है - जो जलवायु कार्रवाई के लिए एक गेम-चेंजर है।
- **लागत-कुशल मार्ग:** महंगे इलेक्ट्रोलिसिस का विकल्प प्रदान करता है, जो संभावित रूप से हरित हाइड्रोजन की लागत (वर्तमान में ₹300-₹400/किग्रा) को कम करके 2030 तक ₹100/किग्रा या $1/किग्रा के लक्ष्य की ओर ले जाता है।

स्रोत: पीआईबी

निस्तार

संदर्भ

भारतीय नौसेना को विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड से 'निस्तार' पोत प्राप्त हुआ।

निस्तार के बारे में -

- **'निस्तार' भारत में पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल (DSV) है।**
- 'निस्तार' नाम संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है मुक्ति, बचाव या मोक्ष।
- इस पोत का निर्माण भारतीय नौवहन रजिस्टर (**IRS**) के वर्गीकरण मानकों के अनुरूप किया गया है।
- **यह एक अत्यंत विशिष्ट जहाज है, जो गहरे समुद्र में गोताखोरी और बचाव कार्य करने में सक्षम है, यह एक दुर्लभ क्षमता है जो विश्व स्तर पर केवल कुछ ही नौसेनाओं के पास है।**

निस्तार की मुख्य विशेषताएं -

- **आयाम**: 118 मीटर लंबा और लगभग 10,000 टन वज़नी।
- उन्नत डाइविंग सिस्टम से लैस, 300 मीटर की गहराई तक डीप सी सैचुरेशन डाइविंग की सुविधा देता है।
- 75 मीटर तक डाइविंग ऑपरेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक साइड डाइविंग स्टेज है।
- **डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल (DSRV)** के लिए 'मदर शिप' के रूप में कार्य करता है, जिसका उपयोग आपात स्थिति में पनडुब्बी कर्मियों के बचाव और निकासी के लिए किया जाता है।
- **सतह से 1000 मीटर नीचे तक गोताखोर निगरानी और बचाव कार्यों में सक्षम रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स (ROV) से सुसज्जित।**
- **लगभग 75% स्वदेशी घटकों से निर्मित, यह आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) की दिशा में एक बड़ा कदम है और मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करता है।**

स्रोत: द हिंदू

प्रतिभा सेतु

संदर्भ

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (**ESIC**) ने हाल ही में यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 451 बीमा चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती करके सुर्खियां बटोरीं।

यूपीएससी प्रतिभा सेतु क्या है?

- **UPSC PRATIBHA Setu का पूर्ण रूप है: Professional Resource And Talent Integration – Bridge for Hiring Aspirants**, जिसका हिंदी में आशय है – **प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु एक व्यावसायिक संसाधन और प्रतिभा एकीकरण सेतु**।
- यह यूपीएससी द्वारा शुरू किया गया एक प्रतिभा-सेतु मंच है, जो सत्यापित नियोक्ताओं को उन अभ्यर्थियों से जोड़ता है, जिन्होंने यूपीएससी प्रारंभिक और बाद के चरणों को उत्तीर्ण किया, लेकिन अंतिम मेरिट सूची में स्थान नहीं बना पाए।
- इसका उद्देश्य उच्च प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों को वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करना है, जो अंतिम चयन से चूक गए थे।

पृष्ठभूमि और विकास -

- **मूल रूप से 20 अगस्त 2018 को संयुक्त चिकित्सा सेवाओं जैसी कुछ परीक्षाओं के लिए सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना (PDS) के रूप में लॉन्च किया गया था।**
- इसकी सफलता के कारण, इस योजना का नाम बदलकर प्रतिभा सेतु कर दिया गया, जिससे इसका दायरा सिविल सेवा, इंजीनियरिंग सेवा आदि जैसी कई परीक्षाओं तक विस्तारित हो गया।
- यह केवल डेटा प्रकटीकरण से सक्रिय प्रतिभा मिलान तक के परिवर्तन को दर्शाता है।

कौन पंजीकरण करा सकता है?

- वे अभ्यर्थी जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा के सभी चरणों (जैसे, सीएसई, आईईएस, आईएफएस, सीएपीएफ, भू-वैज्ञानिक, सीडीएस, सीएमएस) को उत्तीर्ण किया, लेकिन अंतिम सूची में अनुशंसित नहीं किए गए।
- भागीदारी स्वैच्छिक और सहमति-आधारित है, जिससे डेटा गोपनीयता और उम्मीदवार नियंत्रण सुनिश्चित होता है।
- पंजीकरण के लिए पात्र नियोक्ताओं में मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय और निजी फर्म शामिल हैं।
    - निजी कंपनियों को अपने सीआईएन (कॉर्पोरेट पहचान संख्या) का उपयोग करके पंजीकरण करना होगा, जिसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के माध्यम से सत्यापित किया जाता है।

प्लेटफ़ॉर्म कैसे काम करता है -

- पंजीकृत नियोक्ताओं को 10,000 से अधिक उच्च प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों के डेटाबेस को ब्राउज़ करने के लिए सुरक्षित लॉगिन पहुंच मिलती है।
- नियोक्ता उम्मीदवार का बायोडाटा, शैक्षिक योग्यता, परीक्षा विवरण और संपर्क जानकारी देख सकते हैं।
- यह प्लेटफॉर्म नौकरी की आवश्यकताओं के अनुसार उम्मीदवारों का मिलान करने में मदद करने के लिए अनुशासन-वार फ़िल्टरिंग प्रदान करता है।
- नियोक्ता उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, इच्छा सूची में डाल सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं, तथा साक्षात्कार और भर्ती के लिए सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं।

प्रमुख विशेषताएँ -

- सुचारू नियोक्ता नेविगेशन और उम्मीदवार प्रबंधन के लिए सुरक्षित, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड।
- सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए सिविल सेवा स्तर की प्रतिभा तक पहुंच।

- कुशल प्रतिभा उपयोग को प्रोत्साहित करता है और राष्ट्र के व्यापक कौशल परिनियोजन लक्ष्यों का समर्थन करता है।

स्रोत: **टाइम्स ऑफ इंडिया**

क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी(Chronic Venous Insufficiency-CVI)

संदर्भ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को हाल ही में क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी (CVI) नामक बीमारी का पता चला है, जो एक ऐसी चिकित्सीय स्थिति है जो नसों में रक्त प्रवाह को प्रभावित करती है।

क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी(CVI) क्या है?

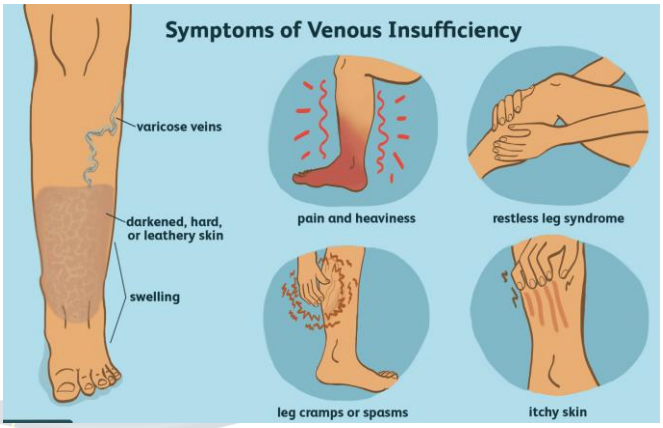

- **CVI तब होता है जब पैरों की नसें हृदय तक रक्त को कुशलतापूर्वक वापस भेजने में विफल हो जाती हैं।**
- सामान्य स्थिति में नसों के वाल्व रक्त को केवल एक दिशा में – हृदय की ओर – बहने देते हैं।
- लेकिन **CVI** में, ये वाल्व कमजोर या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे रक्त उल्टी दिशा में बहने लगता है और पैरों में जमा हो जाता है।
- यह स्थिति आमतौर पर जानलेवा नहीं होती, लेकिन इससे दर्द, सूजन, पैरों में ऐंठन, त्वचा का रंग बदलना, वैरिकोज़ नसें (फूली हुई नसें) और पैरों में घाव (अल्सर) हो सकते हैं।

जोखिम में कौन है?

- निम्नलिखित व्यक्तियों में CVI विकसित होने की संभावना अधिक होती है:
  - अधिक वजन वाले व्यक्ति
  - गर्भवती महिलाएं
  - वे व्यक्ति जिनका शिरा(**veins**) संबंधी समस्याओं का पारिवारिक इतिहास है
- यह जोखिम उन लोगों में भी बढ़ जाता है जिनमें:
  - पैर में चोट लगी
  - पैर की सर्जरी हुई
  - रक्त के थक्के का अनुभव
- CVI वृद्ध वयस्कों में आम है, जो लगभग 20 में से 1 वयस्क को प्रभावित करता है।

CVI के लिए उपचार के विकल्प -

- जीवनशैली में परिवर्तन उपचार की पहली पंक्ति है:
  - नियमित शारीरिक गतिविधि
  - पैरों को ऊपर उठाना
  - वजन नियंत्रण
- चिकित्सा उपचारों में शामिल हैं:
  - रक्त प्रवाह में सुधार करने वाली दवाएं
  - संपीड़न चिकित्सा, नसों को सहारा देने के लिए तंग मोजे या पट्टियों का उपयोग करना
- गंभीर मामलों में, शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं पर विचार किया जा सकता है।

स्रोत: इंडियनएक्सप्रेस

स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय (SPS)

संदर्भ

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच **स्वच्छता और पादप स्वच्छता (Sanitary and Phytosanitary-SPS) उपायों** पर मतभेद जारी है, विशेष रूप से कीटनाशक अवशेष सीमा और एफ्लाटॉक्सिन स्तर जैसे सख्त ईयू खाद्य सुरक्षा मानकों पर, जिससे भारत से कृषि निर्यात प्रभावित हो रहा है।

SPS समझौते के बारे में -

- **SPS समझौता विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अंतर्गत एक संधि है।**
- विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के साथ ही **1 जनवरी 1995 को लागू** हुआ।
- यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खाद्य सुरक्षा तथा पशु एवं पौध स्वास्थ्य मानकों के लिए नियम निर्धारित करता है।

SPS समझौते के प्रमुख प्रावधान -

- **वैज्ञानिक आधार**
    - **SPS** उपाय वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए और पर्याप्त साक्ष्य द्वारा समर्थित होने चाहिए।
    - अपर्याप्त साक्ष्य के मामलों में अनंतिम उपायों की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन उचित समय के भीतर उनकी समीक्षा की जानी चाहिए।
- **सामंजस्य**

    - सदस्य देशों को अपने SPS उपायों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
    - प्रमुख मानक-निर्धारण निकायों में शामिल हैं:
        - कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग (खाद्य सुरक्षा)
        - OIE (विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन)
        - IPPC (अंतर्राष्ट्रीय पादप संरक्षण सम्मेलन)
- **समानक**
    - यदि अन्य देश समान स्तर की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करते हैं तो देशों को उनके समकक्ष SPS उपायों को स्वीकार करना चाहिए, भले ही उनके तरीके अलग-अलग हों।
- **जोखिम आकलन**
    - स्वास्थ्य सुरक्षा के उचित स्तर का निर्धारण करने के लिए वैज्ञानिक जोखिम आकलन करना होगा।
    - कीटों, बीमारियों और प्रदूषकों के प्रभाव पर विचार किया जाता है।
- **क्षेत्रीयकरण**
    - कीट या रोग मुक्त क्षेत्रों को मान्यता देनी चाहिए, भले ही ये किसी देश या देशों के समूह के भीतर विशिष्ट क्षेत्र ही क्यों न हों।
- **पारदर्शिता**
    - SPS उपायों में परिवर्तन के बारे में विश्व व्यापार संगठन को सूचित करना होगा।
    - उन्हें विश्व व्यापार संगठन की SPS अधिसूचना प्रणाली के माध्यम से विनियामक जानकारी भी साझा करनी होगी।
- **विवाद समाधान**
    - यदि विवाद उत्पन्न होता है और परामर्श विफल हो जाता है, तो मामले को विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान निकाय (डीएसबी) में ले जाया जा सकता है।

स्रोत: **इंडियनएक्सप्रेस**

पोलावरम बनकाचेरला लिंक परियोजना (PBLP)

संदर्भ

केंद्र ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच अंतर-राज्यीय जल विवादों - विशेष रूप से पोलावरम-बनकाचेरला लिंक परियोजना - की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के गठन की घोषणा की है।

बनकाचेरला जलाशय परियोजना के बारे में -

- **यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित एक सिंचाई परियोजना, जिसके तहत गोदावरी नदी के अतिरिक्त जल को सूखाग्रस्त रायलसीमा क्षेत्र में भेजा जाएगा।**
- **स्थान**: बनाकाचेरला, नंदयाल जिला, आंध्र प्रदेश।
- गोदावरी-कृष्णा-पेन्ना नदी संपर्क के माध्यम से जल हस्तांतरण शामिल है।

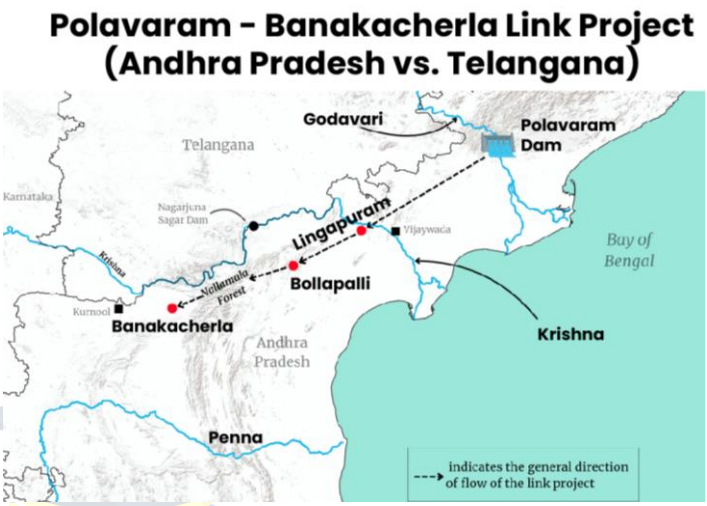

शामिल राज्य -

- **आंध्र प्रदेश**: परियोजना कार्यान्वयन राज्य।
- **तेलंगाना**: राज्य ने कानूनी और पर्यावरणीय चिंताओं का हवाला देते हुए आपत्ति जताई।

परियोजना की विशेषताएं -

- **नदी मोड़ योजना**: पोलावरम दाहिनी मुख्य नहर की क्षमता 17,500 से बढ़ाकर 38,000 क्यूसेक की जाएगी।
  - थाटीपुडी लिफ्ट नहर का जल स्तर 1,400 से बढ़ाकर 10,000 क्यूसेक किया गया।
  - बोल्लापल्ली में एक जलाशय का निर्माण, जिससे नल्लामाला वन से होकर एक सुरंग के माध्यम से पानी को उठाकर बनकाचेरला तक पहुंचाया जा सके।
- **लिफ्ट स्टेशन**:
  - **पांच प्रमुख लिफ्ट बिंदु:** हरिश्चंद्रपुरम, लिंगपुरम, व्यंदन, गंगीरेड्डीपालेम, नकीरेकल्लू।
- **नदी संपर्क**:
  - गोदावरी → कृष्णा → पेन्ना को जोड़ता है, जिससे रायलसीमा तक जल प्रवाह सुगम हो जाता है।

तेलंगाना द्वारा उठाई गई चिंताएँ -

- **आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 का उल्लंघन**: तेलंगाना का तर्क है कि परियोजना में अंतर-बेसिन हस्तांतरण के लिए अधिनियम के तहत आवश्यक अनिवार्य अनुमोदन का अभाव है।
- **नियामक निकायों से मंजूरी नहीं**: निम्नलिखित से अनुमोदन का अभाव:
  - कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB)
  - गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (GRMB)
  - केंद्रीय जल आयोग (CWC)
- **गोदावरी न्यायाधिकरण आवंटन की अनदेखी**: गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा तेलंगाना को 1,486 टीएमसीएफटी में से 968 टीएमसीएफटी आवंटित किया गया था।
  - दावा है कि अधिशेष जल अनुमान को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है।
- **तेलंगाना सिंचाई परियोजनाओं के लिए खतरा**: आशंका है कि जल परिवर्तन से गोदावरी के जल पर निर्भर जलाशयों और सिंचाई योजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

स्रोत: न्यूज़ऑनएयर

संक्षेप में समाचार

महिला आरोग्यम कक्ष

समाचार? विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग ने महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन किया।
इसके बारे में -

- **उद्देश्य:** यह अपनी तरह की पहली पहल है जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल कल्याण को संस्थागत बनाना है।
    - विभाग की महिला कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से समर्पित स्वास्थ्य, फिटनेस और कल्याण स्थान के रूप में कार्य करता है।
- **मुख्य उद्देश्य:**
    - महिला कर्मचारियों के लिए शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देना।
    - जिम उपकरण और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए निजी स्तनपान कक्ष जैसी समावेशी सुविधाएं प्रदान करना।
    - लिंग-संवेदनशील कार्यस्थलों के प्रति प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करना और फिट इंडिया मूवमेंट और विकसित भारत के व्यापक दृष्टिकोण का समर्थन करना।

स्रोत: पीआईबी

एलोग्राफा इफ्यूसोरेडिका(Allographa effusosoredica)

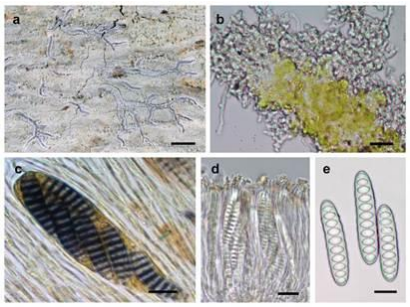

खबर? भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने पश्चिमी घाट से लाइकेन की एक पहले से अज्ञात प्रजाति, एलोग्राफा इफ्यूसोरेडिका की खोज की है।
प्रजाति के बारे में -

- **वर्गीकरण एवं विशेषताएँ:**
    - एक क्रस्टोज़ लाइकेन (सतहों पर पतली और पपड़ी जैसी वृद्धि)।
    - इसकी विशेषता इफ्यूज़ सोरेडिया (चूर्ण जैसी प्रजनन संरचनाएँ) और दुर्लभ रासायनिक लक्षण हैं।
    - इसमें नॉरस्टिक्टिक अम्ल होता है, जो एक अपेक्षाकृत दुर्लभ लाइकेन मेटाबोलाइट है।
    - आकारिकी की दृष्टि से ग्राफिस ग्लौसेसेंस जैसा, लेकिन जातिवृत्तीय दृष्टि से एलोग्राफा ज़ैंथोस्पोरा के निकट।
    - शैवाल सहजीवी की पहचान ट्रेंटेपोहलिया की एक प्रजाति के रूप में की गई है।
- **महत्व:**
    - **आणविक डेटा द्वारा समर्थित भारत की पहली एलोग्राफा प्रजाति।**
    - लाइकेन-शैवाल सहजीवन और स्थानीय रूप से अनुकूलित फोटोबायोन्ट की समझ को बढ़ाता है।
    - **वर्गीकरण संबंधी समृद्धि में वृद्धि:** भारत से 53वीं एलोग्राफा प्रजाति की रिपोर्ट, पश्चिमी घाट से 22वीं।

लाइकेन क्या हैं?

- लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो निम्नलिखित के बीच सहजीवी संबंध से बनते हैं:
    - एक कवक (माइकोबायोन्ट): संरचना और सुरक्षा प्रदान करता है।
    - एक प्रकाश संश्लेषक साझेदार (फोटोबायोन्ट): आमतौर पर हरे शैवाल या सायनोबैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का उत्पादन करते हैं।

स्रोत: पीआईबी

संपादकीय सारांश

भारतीय असमानता और विश्व बैंक के दावे

संदर्भ

भारत में असमानता पर बहस तब फिर से शुरू हो गई जब 2025 की विश्व बैंक की रिपोर्ट में गरीबी और उपभोग असमानता में उल्लेखनीय कमी आने का दावा किया गया, जिससे आंकड़ों की वैधता और व्यापक व्याख्याओं के बारे में प्रशंसा और संदेह दोनों पैदा हुए।

विश्व बैंक के निष्कर्ष -

- **भारत ने 2011 और 2023 के बीच लगभग 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर, अत्यधिक गरीबी को लगभग समाप्त कर दिया है।**
- **उपभोग असमानता में कमी आई है, गिनी गुणांक 28.8 (2011-12) से घटकर 25.5 (2022-23) हो गया है।**
- आबादी के सबसे निचले 20% लोगों ने, मुफ्त भोजन और नकद हस्तांतरण को छोड़कर भी, आहार और संपत्ति में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है।
- उपभोग के संदर्भ में भारत अब वैश्विक स्तर पर शीर्ष चार सबसे कम असमान देशों में शामिल है।
- **ये निष्कर्ष HCES 2022-23 पर आधारित हैं, जिसमें संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि (MMRP) का उपयोग किया गया था - एक ऐसी विधि जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है।**

निष्कर्षों से संबंधित मुद्दे -

- **HCES** अभिजात वर्ग/शीर्ष 5% उपभोग को पूरी तरह से नहीं दर्शाता है, जिससे वास्तविक असमानता का कम आकलन हो सकता है।
- उपभोग असमानता ≠ आय असमानता; आय संबंधी आंकड़ों का अभाव है, और तुलना भ्रामक हो सकती है।
- विश्व असमानता प्रयोगशाला (WIL) के आय असमानता के अनुमान अविश्वसनीय मान्यताओं पर आधारित हैं, जैसे कि अधिकांश परिवार अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं।
    - उदाहरण के लिए, WIL के अनुमान बताते हैं कि 70-80% परिवार साल दर साल अपनी कमाई से अधिक खर्च करते हैं - जो तार्किक रूप से असंगत धारणा है।
- WIL कर-पूर्व आय का उपयोग करता है, तथा भारत के पर्याप्त कल्याणकारी हस्तांतरण और कर पुनर्वितरण को नजरअंदाज करता है, जिससे कथित असमानता कम हो जाती है।
    - उदाहरण के लिए, निर्धारण वर्ष 2023-24 में, शीर्ष 1% करदाताओं ने कुल करों का 72.77% भुगतान किया; लेकिन यह WIL के कर-पूर्व असमानता आंकड़ों में परिलक्षित नहीं होता है।
- मीडिया अक्सर डेटा की खामियों या कर-पश्चात वास्तविकताओं को स्वीकार किए बिना शीर्ष 1% शेयरों पर अधिक जोर देकर असमानता को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है।

आगे की राह -

- आय वितरण पर सीधे नज़र रखने के लिए आधिकारिक, मजबूत आय सर्वेक्षण विकसित करना।
- असमानता माप में कर-पश्चात और हस्तांतरण-पश्चात प्रभावों को शामिल करना।
- उच्च आय वाले परिवारों और अभिजात वर्ग के उपभोग पर डेटा संग्रह में सुधार करना।
- सार्वजनिक चर्चा में आय और उपभोग-आधारित असमानता के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करना।
- संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार तक समान पहुंच पर नीति को केंद्रित करना।
- शेष कमियों के प्रति सतर्क रहते हुए प्रगति को पहचानना और उसका जश्न मनाना।

स्रोत: द हिंदू